



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, १९ मार्च, १९९६/ २९ फाल्गुन, १९१७

हिमाचल प्रदेश सरकार

उद्यान विभाग

अधिसूचना

शिमला-२, २९ जनवरी, १९९५

संख्या एच०डी०सी०बी०(४)-२०/९५.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद ३०९ के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उद्यान विभाग, हिमाचल प्रदेश में चौकीदार/बलीनर/सफाई कर्मचारी पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपोद्घ-‘अ’ के अनुसार भर्ती एवं प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

१. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(१) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश उद्यान विभाग चौकीदार/बलीनर/सफाई कर्मचारी वर्ग-४ (असाधारण) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, १९९६ है।

(२) ये नियम तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

10. भर्ती की पद्धति :

भर्ती सीधी होगी अथवा प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।

शत प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।

11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण की दशा में क्षेत्रियों, जिसमें प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण किया जाएगा।

लागू नहीं।

12. यदि विभागोंय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना।

लागू नहीं।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।

जैसा कि विधि द्वारा अपेक्षित है

14. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षा :

किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी निम्नलिखित अवश्य होना चाहिए :

(क) भारत का नागरिक, या

(ख) नेपाल की प्रजा, या

(ग) भूटान की प्रजा, या

(घ) तिब्बती शरणार्थी जो 1 जनवरी, 1962 से पूर्व भारत में स्थायी रूप से निवास के आशय से प्रवास के लिए आया हो, या

(ङ) भारतीय मूल का कोई व्यक्ति जिसने पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीका के देशों कीनिया, युगांडा, युनाईटेड रिपब्लिक ऑफ रुजानिया (पहले तांगानिका तथा जंजीबार) जाम्बिया, मालावी, जेयरे तथा ईथोपिया से भारत में स्थायी निवास के आशय से प्रवास किया हो : परन्तु प्रवर्ग (ख), (ग), (घ) और (ङ) के अभ्यर्थी ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके पक्ष में भारत सरकार द्वारा मात्रता प्रमाण-पत्र जारी किया हो।

ऐसे अभ्यर्थी जो जिनके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा मंचालित परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश किया जा सकेगा किन्तु उसे नियुक्ति का प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा पात्रता का अपेक्षित प्रमाण-पत्र जारी किए जाने के पश्चात् ही दिया जाएगा।

15. मीट्री भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन । लागू नहीं ।
16. आरक्षण उक्त भेदा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों, पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए आरक्षण के वाकत जारी किए गये आदेशों के अधीन होगी ।
17. शिथिल करने की शक्ति जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो यह कारणों को अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा इन नियमों के निम्नी उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की वाकत, शिथिल कर सकेगी ।

[Authoritative English Text of H. P. Govt. notification No. HTC-B (4)-20/95, dated 29th January, 1996, as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India].

HORTICULTURE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, 29th January, 1996

No. HTC-B (4)-20/95.—The Governor of Himachal Pradesh, in exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Chokidar/Cleaner/Sweeper Class-IV (Non-Gazetted) in the Department of Horticulture, Himachal Pradesh as per Annexure-‘A’ attached to this Notification namely :—

1. *Short title and commencement.*—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Horticulture Department Chokidar/Cleaner/Sweeper Class-IV (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1996.

2. These shall come into force at once.

2. *Repeal and savings.*—(1) The Himachal Pradesh Horticulture Class-IV Service (Recruitment and Promotion and certain conditions of service) Rules, 1973, notified vide this Department Notification No. 16/1/73-Hort. (Sectt.) dated 3-9-1973 are hereby repealed to the extent these pertain to the posts of Chokidar/Cleaner/Sweeper.

(2) Nothing withstanding such repeal, any appointment made, anything done or any action taken under the repealed rules shall be deemed to have been validly made, done or taken under these rules.

By order,

Sd/-

Commissioner-cum-Secretary.

14. Essential requirement for a direct recruitment.

A candidate for appointment to any service or post must be :—

- (a) a citizen of India, or
- (b) a subject of Nepal, or
- (c) a subject of Bhutan, or
- (d) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India;
- (e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, East African countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia with the intention of permanently settling in India:

Provided that a candidate belonging to categories (b), (c), (d) and (e) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview conducted by the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government of India.

15. Selection for appointment to the post by direct recruitment.

Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of *viva voce* test and if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/syllabus, etc. of which, will be determined by the Commission/other recruiting authority as the case may be.

16. Reservation

The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Backward Classes and other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Power to relax

Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do it may by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision of these rules with respect to any class or category of persons or posts.